गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित होता दैनिक

संपादक : श्री मनोजकुमार चंपकलाल शाह

रजी.ओफिस : टी.एफ-०१,नानकराम सुपर मार्केट,रामनगर,साबरमती,अहमदाबाद- ३८० ००५.गुजरात,भारत.

फोन /फेक्स : (०७९) २७५७ ३३०७, ९०१६३ ३३३०७ (मो) ९३२८३ ३३३०७, ९८२५३ ३३३०७, Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Website : www.garvigujarat.co.in

वर्ष : 08 | अंक : 279 | दि. 08-02-2019 शुक्रवार | वि.सं. 2075 | महासुद -०३ | पाना : 04 | किंमत : 00.50 पैसा

आरबीआई की एमपीसी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया

रीपो और रिवर्स रेपो रेट कम किया गया : लोन सस्ता होगा

छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रिपो रेट कम करके ६.२५ फीसदी तथा रिवर्स रिपो रेट छह फीसदी हुआ : सीआरआर को बरकरार रखा गया

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रीपो रेट में ०.२५% कटौती का फैसला किया। इसके साथ ही, अब रीपो रेट ६.५०% से घटकर ६.२५% हो गया। एमपीसी के छह में से चार सदस्यों ने रीपो रेट में कटौती का समर्थन किया जबकि दो अन्य सदस्यों, विरल आचार्य और चेतन घाटे रेट कट के पक्ष में नहीं थे। नई मौद्रिक नीति के तहत रिवर्स रीपो रेट घटकर ६ प्रतिशत जबकि बैंक रेट ६.५० प्रतिशत पर आ गया है। दरअसल, रीपो रेट ब्याज की वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को फंड मुहैया कराता है। चूंकि रीपो रेट घटने से बैंकों को आरबीआई से सस्ती फंडिंग प्राप्त हो सकेगी, इसलिए बैंक भी अब कम ब्याज दर पर लोन ऑफर कर पाएंगे। इससे नया लोन सस्ता हो जाएगा जबकि लोन ले चुके लोगों को या तो ईएमआई में या रीपेमेंट पीरियड में कटौती का फायदा मिल सकता है। बहरहाल, एमपीसी ने उम्मीद के मुताबिक नीतिगत रुख को नपी-तुली कठोरता बरतने को बदल कर तटस्थ कर दिया। इस बार विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई थी कि एमपीसी मौद्रिक स्थिति के संबंध में अपने मौजूदा सोच-विचार वाले रुख को तटस्थ कर सकती है क्योंकि मुद्रास्फीति दर नीचे बनी हुई है।

५, ६ और ७ फरवरी को चली छह सदस्यीय एमपीसी की बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। आरबीआई गवर्नर बनने के बाद यह उनका पहली एमपीसी बैठक थी। समिति ने कहा है कि ये फैसेल मीडियम टर्म में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा महंगाई दर को ४ प्रतिशत (२ प्रतिशत कम-ज्यादा) तक रखने के लक्ष्य के मद्देनजर लिए गए हैं। खाद्य कीमतों में लगातार गिरावट के चलते खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर २०१८ में २.१९ प्रतिशत रही जो १८ माह का निचला स्तर है। बता दें कि यह चालू वित्त वर्ष की छठी और आखिरी मौद्रिक नीति समीक्षा है। आरबीआई ने पिछले तीन बार से अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रीपो रेट को लेकर स्थिति पहले जैसी बरकरार रखी थी। उससे पहले चालू वित्त वर्ष की अन्य दो समीक्षाओं में प्रत्येक बार उसने दरों में ०.२५ प्रतिशत की वृद्धि की थी। दिसंबर २०१८ में अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन वादा किया था कि अगर मुद्रास्फीति का जोखिम नहीं हुआ तो वह दरों में कटौती करेगा।

बिहार के शेल्टर होम का मामला

जांच अधिकारी के तबादले से SC नाराज, नागेश्वर राव तलब

रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुप्रीम के पहले दिए आदेशों का उल्लंघन किए जाने को गंभीरता से लिया

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे अधिकारी का ट्रांसफर किए जाने पर सीबीआई को फटकार लगाई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के तत्कालीन अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव को अवमानना का नोटिस भेजा और उन्हें १२ फरवरी को पेश होने का आदेश दिया। दरअसल, तत्कालीन सीबीआई चीफ ने एजेंसी के पूर्व संयुक्तनिदेशक एके शर्मा का ट्रांसफर कर दिया था, जो बिहार के शेल्टर होम मामलों की जांच कर रहे थे। सुप्रीम ने कहा कि एजेंसी से बाहर अधिकारी का स्थानांतरण करना कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए दो आदेशों का उल्लंघन किए जाने को गंभीरता से लिया। सुप्रीम ने कोर्ट से बिना मंजूरी लिए १७ जनवरी को शर्मा को तबादला CRPF में किए जाने पर राव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया। बेंच में जस्टिस दीपक मिश्र और संजीव खन्ना भी शामिल थे। बेंच ने सीबीआई निदेशक को एके शर्मा का तबादला जांच एजेंसी के बाहर करने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के नाम बताने का भी निर्देश दिया। इस दौरान SC ने अपने पहले के आदेशों का स्पष्ट संदर्भ दिया, जिनमें सीबीआई से बिहार शेल्टर होम मामलों की जांच करने वाली टीम से एके शर्मा को नहीं हटाने को

कहा गया था। इसके बावजूद तबादला होने पर कोर्ट से गहरी नाराजगी जताई। राव के अलावा बेंच ने सीबीआई के दूसरे अधिकारियों को भी १२ फरवरी को पेश होने के लिए कहा, जो ट्रांसफर की प्रक्रिया में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के उल्लंघन के लिए सीबीआई अभियोजन निदेशक प्रभारी एस. भासू राम को भी मौजूद रहने का निर्देश दिया।

कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक अधिवेशन में ऐलान

सत्ता में लौटे तो खत्म करेंगे तीन तलाक कानून : कांग्रेस

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा ऐलान करते हुए सत्ता में आने पर तीन तलाक कानून खत्म करने की बात कही है। दिल्ली में पार्टी के अल्पसंख्यक अधिवेशन के दौरान पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में सिलचर से सांसद और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देब की ओर से यह ऐलान किया गया। अल्पसंख्यकों के बीच पार्टी का आधार मजबूत करने के मकसद से गुरुवार को राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया था। अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि आए राहुल ने इस दौरान मोदी सरकार पर तीखे वार किए। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का चेहरा ध्यान से देखें तो आपको घबराहट दिखेगी। राहुल ने कहा कि मोदी जी समझ चुके हैं कि देश के लोगों को तोड़कर पीएम नहीं बना जा सकता है। बीजेपी वाले कहते थे कि मोदी १५ साल तक पीएम रहेंगे, लेकिन कांग्रेस ने उनके इस दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। पहले बीजेपी के लोग कहते थे, अच्छे दिन आएंग, लेकिन अब देश के लोग कहते हैं, चौकीदार चोर है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये देश किसी एक धर्म का नहीं है। यह देश हिंदुस्तान के हर व्यक्तिका है। लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच की है। देश अल्पसंख्यकों ने भी देश को बनाने का काम किया है। एक विचारधारा कहती है कि देश सोने की चिड़िया है, जिसका मतलब है कि देश एक प्रॉडक्ट है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश एक नदी है, जिसमें सभी को जगह मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस के लोग चाहते हैं कि सरकार नागपुर से चले। नरेंद्र मोदी देश को आगे से चलाएंगे और मोहन भागवत देश को पीछे से चलाना चाहते हैं। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का चेहरा ध्यान से देखें तो आपको घबराहट दिखेगी। राहुल ने कहा कि मोदी जी समझ चुके हैं कि देश के लोगों को तोड़कर पीएम नहीं बना जा सकता है। बीजेपी वाले कहते थे कि मोदी १५ साल तक पीएम रहेंगे, लेकिन कांग्रेस ने उनके इस दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। पहले बीजेपी के लोग कहते थे, अच्छे दिन आएंग, लेकिन अब देश के लोग कहते हैं, चौकीदार चोर है।राहुल ने कहा, हमारा संविधान कांग्रेस पार्टी का नहीं, बल्कि देश का है। उसकी रक्षा करना सभी पार्टियों की है। उन्होंने कहा कि आने वाले ३ महीने में देश इन्हें (बीजेपी) बताने जा रहा है कि देश ऊपर है और ये नीचे हैं। आज लोकसभा में गडकरी ने अच्छा भाषण दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरीफ करते हुए कहा, लोग कह रहे हैं कि गडकरी जी अकेले ऐसे मंत्री हैं, जो सबका काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि इस सरकार में ज्यादातर मंत्री भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहे हैं। राहुल ने कहा कि पांच साल पहले नरेंद्र मोदी की रेप्युटेशन बहुत अच्छी थी। लेकिन अपनी सरकार में भ्रष्टाचार की वजह से प्रधानमंत्री आज बोल भी नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने देश को रास्ता दिखाया है। जब भी देश मुश्किल में होता है तो देश कांग्रेस की तरफ देखता है। पांच साल में मोदी ने देश को सिर्फ नोटबंदी दी।

सदगुरु जग्गी वासुदेव की राम मंदिर पर प्रतिक्रिया

मुस्लिमों को परिसर के बाहर अतिरिक्त जमीन दे सकते हैं

राम मंदिर कभी चुनाव का मुद्दा नहीं था, कोर्ट को इसे तय करना है और कोर्ट इसे जल्द से जल्द तय कर दे

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने राम मंदिर निर्माण पर कहा कि वहां मंदिर ही बनना चाहिए। यह बहुत विचित्र है कि कोर्ट यह तय करेगा कि वहां राम का जन्म हुआ था या नहीं। एएसआई का भी कहना है कि वहां एक मंदिर ही था। अब कोर्ट का कहना है कि यह जमीन से जुड़ा मामला है। जो भी है, लेकिन जल्द से जल्द यह सेटल होना चाहिए। राम मंदिर कभी चुनाव का मुद्दा नहीं था, कोर्ट को इसे तय करना है और कोर्ट इसे जल्द से जल्द तय कर दे। वहां मंदिर बना दो और खत्म करो। वहां पूरी जमीन में से सिर्फ २.७ एकड़ ही विवादित जमीन है। अगर इसका एक तिहाई हिस्सा मुस्लिमों का है तो आदर्श स्थिति है कि मुस्लिमों को २.७ एकड़ जमीन में जितना हिस्सा बनता है उससे अधिक हिस्सा गैर-विवादित जमीन में से मिलना चाहिए। क्या हमारे यहां भूमि विवाद ऐसे ही नहीं सुलझाए जाते हैं हिंदुओं के लिए इस जमीन के साथ भावनाएं जुड़ी हैं क्योंकि उनकी मान्यता है कि राम लला ने वहीं जन्म लिया था। एएसआई का भी कहना है कि वहां एक मंदिर ही था। अब कोर्ट का कहना है कि यह जमीन से जुड़ा मामला है। जो भी है, लेकिन जल्द से जल्द यह सेटल होना चाहिए। राम मंदिर कभी चुनाव का मुद्दा नहीं था, कोर्ट को इसे तय करना है और कोर्ट इसे जल्द से जल्द तय कर दे। मुस्लिमों के साथ इस तरह की कोई भावना नहीं जुड़ी हुई। कोर्ट को चुनाव से पहले ही इस पर फैसला देना चाहिए। सबरीमाला मुद्दा कोई लैंगिक भेदभाव का मामला नहीं है। हमारे यहां देवियों के कहीं अधिक मंदिर हैं। मंदिर कोई प्रार्थना की जगह नहीं होती है, यहां पर आप सिर्फ दर्शन के लिए आते हैं। सबरीमाला अकाल ब्रह्मचारी का स्थान है। यह उनका निजी स्थान है उनका शयनकक्ष। आप वहां क्यों जाना चाहती हैं कोर्ट को यह नहीं तय करना चाहिए कि एक मंदिर के अंदर क्या हो या क्या नहीं हो। इससे खजाने पर प्रतिकूल असर पड़ता है और किसानों की समस्याएं कर्ज माफी के जरिए खत्म नहीं होंगी। किसानों ये कहें कि आप ऋण लो और फिर उसे मत चुकाओ। अगर आप एक बार पैसे लेकर फिर उसे कभी नहीं चुकाने का चलन शुरू कर दोगे तो कोई कब तक आपको पैसे देते रहेगा अब आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग को रिजर्वेशन मिले।

एनआईए रिपोर्ट में हुआ खुलासा

इंटरनैशनल बॉर्डर से आतंकी कर रहे हैं कश्मीर में घुसपैठ

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, यह सवाल कई दिनों से उठ रहा है कि जब कश्मीर में आतंकी लगातार मार गिराए जा रहे हैं और एलओसी पर कड़ी चौकसी के चलते घुसपैठ करने में नाकाम हैं तो फिर घाटी में इनकी संख्या कम क्यों नहीं हो रही है एनआईए रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वह इस सवाल का जवाब देता है। एनआईए रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से आतंकी इंटरनैशनल बॉर्डर के जरिए लगातार घुसपैठ कर रहे हैं, खासकर जम्मू फ्रंटियर के सांबा-कठुआ से। एनआईए की रिपोर्ट की कॉपी इस रिपोर्टर ने देखी है और रिपोर्ट में इसका भी खुलासा हुआ है कि २०१७ से अब तक७ बार में ३३ पाकिस्तानी आतंकियों को टूक के जरिए कश्मीर तक पहुंचाया गया है। एनआईए ने झज्जर कोटली और नागरोटा आतंकी हमले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की। इस केस में आरोपियों के पास से बरामद सामानों से कई जानकारियां मिलीं। पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के चश्मदीदों से बातचीत में भी एनआईए को कई अहम जानकारियां मिली हैं। दीनानगर टेरसिस्ट अटैक केस में जो डिवाइस बरामद हुई, उसके जीपीएस डेटा से अहम लीड मिली। साथ ही इन सब केस में कॉल डीटेल रेकॉर्ड और टेक्निकल ऐनालिसिस के जरिए एनआईए को यह पुख्ता हो गया कि किस तरह इंटरनैशनल बॉर्डर के जरिए घुसपैठ हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैश-ए-मोहम्मद ने ओवरग्राउंड वर्कर्स का तगड़ा नेटवर्क तैयार

किया है। जिन्हें पाकिस्तानी आतंकियों को रिसीव करने और फिर जम्मू से ले जाकर कश्मीर पहुंचाने का जिमा दिया जाता है। ओवरग्राउंड वर्कर्स को आतंकी सांबा-कठुआ बेल्ट में नैशनल हाईवे पर बुलाते हैं और वॉट्सऐप के जरिए उन्हें लोकेशन दे दी जाती है। फिर टूक के जरिए ये ओवरग्राउंड वर्कर्स आतंकियों को और उनके असलहे को कश्मीर पहुंचाते हैं। आतंकियों को तड़के २ से ५ बजे के बीच पिक किया जाता है। आतंकी टनल का इस्तेमाल कर इंटरनैशनल बॉर्डर से अंदर घुसते होंगे, इस संभावना से भी रिपोर्ट में इनकार नहीं किया है। रिपोर्ट में पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर से भी घुसपैठ की बात कही गई है। अब तक सातों बार हुई घुसपैठ में पाकिस्तानी आतंकियों को पठानकोट-जम्मू नैशनल हाईवे से पिक किया गया। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर बार आतंकियों ने ५-५ के ग्रुप में घुसपैठ की। २३-२४ अक्टूबर २०१७ को ५ आतंकियों को उनके नेटवर्क द्वारा रिसीव किया गया। ३०-३१ दिसंबर २०१७ की रात को ५ आतंकियों को, १४-१५ जनवरी २०१८ को ५ आतंकियों, १३-१४ मार्च २०१८ को ५ आतंकियों, १३-१४ अप्रैल २०१८ को ५ आतंकियों, १३-१४ मई २०१८ को ५ आतंकियों और ११-१२ सितंबर २०१८ को ३ आतंकियों को रिसीव किया गया। एनआईए रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू रीजन के पार पाकिस्तान में आतंक के नई लॉन्च पैड बने हैं। कठुआ और बामियाल सेक्टर के दूसरी तरफ शकरगढ़, हीरा नगर सेक्टर के दूसरी तरफ सुखमल, सांबा सेक्टर के दूसरी तरफ दुरमान, आरएसपुरा सेक्टर के दूसरी तरफ हेडमराला, अखनूर सेक्टर के दूसरी तरफ बरनाला, सुंदरबनी के दूसरी तरफ पंडोली-नयाली और नौशेरा के दूसरी तरफ समहानी में आतंक के नई ठिकाने बने हैं।

संपादकिय

नागरिकता विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए

यह ठीक नहीं कि तीन तलाक संबंधी विधेयक की तरह से नागरिकता संबंधी विधेयक पर भी पक्ष–विपक्ष के बीच कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है।इसका बडा कारण विभिन्न दलों की ओर से अपने–अपने राजनीतिक हितों को जरूरत से ज्यादा अहमियत दिया जाना है। चूंकि आम चुनाव करीब आ गए हैं इसलिए यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल अपने चुनावी हितों की चिंता करें, लेकिन इस कोशिश में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।नागरिकता संशोधन विधेयक पर विपक्ष की आपत्ति का एक बडा आधार यह है कि आखिर इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी समुदाय के लोगों को ही भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान क्यों है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को बाहर क्यों रखा गया है ? सैद्धांतिक तौर पर यह आपत्ति उचित नजर आती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो इसका औचित्य नहीं नजर आता कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बहुसंख्यकों को वैसी ही रियायत दी जाए जैसी इन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देने की व्यवस्था की गई है।सभी को एक समान नजर से देखने की मांग करने वाले विपक्षी दल इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि उक्त तीनों देशों से प्रताडित होकर भारत की राह देखने वाले मूलत- वहां के अल्पसंख्यक ही होते हैं, न कि बहुसंख्यक।वे इस तथ्य को भी ओझल नहीं कर सकते कि बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ के कारण पश्चिम बंगाल और असम के साथ पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के तमाम इलाकों का सामाजिक संतुलन किस तरह गडबडा गया है। आदर्शवादी सिद्धांत जमीनी हकीकत से मेल भी खाने चाहिए। यह कोई तर्क नहीं हुआ कि भारत दक्षिण एशिया का बडा देश है और उसे उन सभी को शरण देनी चाहिए जो इस देश में बसना चाहता है। भारत का संविधान भारत के लोगों पर लागू होता है, बाहर के नागरिकों पर नहीं और यह तय करना देश विशेष का अधिकार है कि वह किसे शरण दे और किसे नहीं ? आखिर विपक्षी दलों के साथ इस विधेयक का विरोध करने वाले अन्य लोग यह क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि बाहरी लोगों की घुसपैठ और खासकर बांग्लादेशियों की अवैध बसाहट से असम की संस्कृति किस तरह खतरे में पड गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार हुआ उसका एक बडा मकसद असम की मूल संस्कृति को बचाना नहीं है ? सैद्धांतिक तौर पर यह आपत्ति उचित नजर आती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो इसका औचित्य नहीं नजर आता कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बहुसंख्यकों को वैसी ही रियायत दी जाए जैसी इन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देने की व्यवस्था की गई है। सभी को एक समान नजर से देखने की मांग करने वाले विपक्षी दल इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि उक्त तीनों देशों से प्रताडित होकर भारत की राह देखने वाले मूलत- वहां के अल्पसंख्यक ही होते हैं, यह सही है कि असम और पूर्वोत्तर के कुछ अन्य राज्यों में नागरिकता विधेयक का विरोध हो रहा है, लेकिन इसकी वजह वह नहीं है जिसे विपक्षी दल बयान कर रहे हैं। असम और अन्य राज्यों में इस विधेयक का विरोध तो इस आशंका के चलते हो रहा है कि अगर पडोसी देशों के अल्पसंख्यकों को उनके यहां बसा दिया गया तो उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी ? बेहतर हो कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के उन लोगों और समूहों की चिंताओं को दूर करे जो नागरिकता विधेयक का विरोध कर रहे हैं। निःसंदेह उसे विपक्षी दलों से भी व्यापक विचार–विमर्श करना चाहिए ताकि बीच का कोई रास्ता निकल सके। राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया जाए तो ऐसा हो सकता है।

सारधा–रोज वैली जैसे घोटालों की ऐसी जांच न हो जिसमें पीडितों को राहत न मिल सके

हजारों करोड रुपये के चिटफंड घोटालों की सीबीआइ जांच को लेकर ममता और मोदी सरकार के बीच छिडे घमासान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्ष जो मन में आए वह दावा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता कि उन लाखों लोगों के मन में उम्मीद की कोई किरण जगी होगी जिन्हें सारधा और रोज वैली नामक चिटफंड कंपनियों ने लूटा। एक आंकडे के अनुसार इन दोनों चिटफंड कंपनियों ने करीब 22 लाख लोगों के लगभग 20 हजार करोड रुपये हडप किए।इन दिनों भले ही सारधा घोटाले की जांच को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ हो, लेकिन इस घोटाले से बडा घोटाला रोज वैली कंपनी ने अंजाम दिया था। ये दोनों कंपनियां हजारों करोड रुपये की लूट इसलिए आसानी से कर सकीं, क्योंकि उन्होंने तमाम नेताओं के साथ मीडिया के भी कई लोगों को अपने धनबल से संतुष्ट रखा। सारधा घोटाला 2013 में ही सतह पर आ गया था। ममता सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। इस जांच दल के प्रमुख वही राजीव कुमार थे जो इस समय कोलकाता के पुलिस आयुक्त हैं और जिनसे सीबीआइ की पूछताछ को लेकर कोहराम मचा। जब विशेष जांच दल से जांच को नाकाफी बताकर सीबीआइ जांच की मांग हुई तो ममता सरकार ने ऐसी किसी जांच का विरोध किया, लेकिन मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए सीबीआइ जांच के आदेश दिए कि इस घोटाले का दायरा पश्चिम बंगाल के बाहर पडोसी राज्यों में भी फैला हुआ है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारधा के साथ अन्य चिटफंड कंपनियों की भी जांच जरूरी बताई थी इसलिए रोज वैली कंपनी भी सीबीआइ जांच के दायरे में आई। जल्द ही यह पता चला कि रोज वैली कंपनी ने तो कहीं अधिक लोगों को ठगा है। यह सही है कि बीते चार सालों में सारधा और रोज वैली घोटाले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कई लोग जेल भी गए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इन दोनों घोटालों की जांच कब तक जारी रहेगी ? इस बारे में तो दूर–दर तक कोई खबर ही नहीं कि इन दोनों कंपनियों की ठगी का शिकार हुए लाखों लोगों को किसी तरह की कोई राहत कब मिलेगी ? हालांकि सारधा और रोज वैली कंपनियों के संचालकों की तमाम संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक इन कंपनियों की संपत्तियां बेचकर ठगी के शिकार हुए लोगों को राहत देने की कोई कोशिश होती नहीं दिख रही है। इस तरह के घोटालों की वैसी जांच का कोई मतलब नहीं जिसमें पीडित लोगों को राहत मिलने की कोई सूरत न नजर आए। हो सकता है कि सीबीआइ जांच सही दिशा में हो, लेकिन क्या इसकी अनदेखी कर दी जाए कि वह अभी तक वे दस्तावेज भी हासिल नहीं कर सकी है जो राजीव कुमार ने विशेष जांच दल के प्रमुख के नाते सारधा कंपनी के मुखिया सुदीप्त सेन और उसकी सहयोगी देवजानी मुखर्जी से हासिल किए थे। सीबीआइ की मानें तो देवजानी ने यह स्वीकार किया था कि विशेष जांच दल ने उसके पास से एक लाल डायरी और पेन ड्राइव समेत कुछ दस्तावेज जब्त किए थे। यह हैरानी की बात है कि सीबीआइ अभी तक वह लाल डायरी और पेन ड्राइव की ही तलाश कर रही है। माना जाता है कि इसी लाल डायरी और पेन ड्राइव के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सीबीआइ कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करना चाह रही थी। ममता सरकार ने ऐसा नहीं करने दिया और सीबीआइ अधिकारियों को ही बंधक बना लिया। यदि इस बात में तनिक भी सच्चाई है कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार सारधा घोटाले के सुबूत दबाए बैठे हैं तो सीबीआइ को उनसे पूछताछ करने के साथ उन्हें गिरफ्तार करने का भी अधिकार होना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को यह आदेश दिया है कि वह उनसे शिलांग में पूछताछ तो कर सकती है, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकती। जिस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है उसकी प्रगति और साथ ही उसकी दशा–दिशा से उसे परिचित होना चाहिए। हो सकता है कि वह परिचित हो, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं। इन घोटालों का पटाक्षेप होता हुआ भी दिखना चाहिए।

रिवर्स रीपो रेट बरकरार ६ फीसदी

२००६ के बाद रिवर्स रिपो रेट में बदलाव की तारीख

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

रेट (फीसदी)	तारीख
५.५०	२४-०१-२००६
५.७५	०८-०६-२००६
६.००	२५-०७-२००६
५.००	०८-१२-२००८
४.००	०२-०१-२००९
३.५०	०४-०३-२००९
३.२५	२१-०४-२००९
३.५०	१९-०३-२०१०
३.७५	२०-०४-२०१०
४.००	०२-०७-२०१०
४.५०	२७-०७-२०१०
५.००	१६-०९-२०१०
५.२५	०२-११-२०१०
५.५०	२५-०१-२०११
५.७५	१७-०३-२०११
६.२५	०३-०५-२०११
६.५०	१६-०६-२०११
७.००	२६-०७-२०११
७.२५	१६-०९-२०११
७.५०	२५-११-२०११
७.००	१७-०४-२०१२
६.७५	२९-०१-२०१३
६.५०	१९-०३-२०१३
६.२५	०३-०५-२०१३
६.५०	२०-०९-२०१३
६.७५	२९-१०-२०१३
७.००	२८-०१-२०१४
६.७५	१५-०१-२०१५
६.५०	०४-०३-२०१५
६.२५	०२-०६-२०१५
५.७५	२९-०९-२०१५
५.७५	२९-०९-२०१५
६.००	०५-०४-२०१६
५.७५	०४-१०-२०१६
६.००	०६-०४-२०१७
५.७५	०२-०८-२०१७
६.००	०६-०६-२०१८
६.२५	०१-०८-२०१८
६.००	०७-०२-२०१९

रीपो रेट बरकरार ६.२५ फीसदी

२००६ बाद से रीपो रेट में किए बदलाव की तारीख

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

रेट (फीसदी)	तारीख
६.५०	२४-०१-२००६
६.७५	०८-०६-२००६
७.००	२५-०७-२००६
७.२५	३०-१०-२००६
७.५०	३१-०१-२००७
७.७५	३०-०३-२००७
८.००	११-०६-२००८
८.५०	२४-०६-२००८
९.००	२९-०७-२००८
८.००	२०-१०-२००८
७.५०	०३-११-२००८
६.५०	०८-१२-२००८
५.५०	०२-०१-२००९
५.००	०४-०३-२००९
४.७५	२१-०४-२००९
५.००	१९-०३-२०१०
५.२५	२०-०४-२०१०
५.५०	०२-०७-२०१०
५.७५	२७-०७-२०१०
६.००	१६-०९-२०१०
६.२५	०२-११-२०१०
६.५०	२५-०१-२०११
८.००	१७-०४-२०१२
७.७५	२९-०१-२०१३
७.५०	१९-०३-२०१३
७.२५	०३-०५-२०१३
७.५०	२०-०९-२०१३
७.७५	२९-१०-२०१३
७.७५	१८-१२-२०१३
८.००	२८-०१-२०१४
७.७५	१५-०१-२०१५
७.५०	०४-०३-२०१५
७.२५	०२-०६-२०१५
६.७५	२९-०९-२०१५
६.५०	०५-०४-२०१६
६.२५	०४-१०-२०१६
६.००	०२-०८-२०१७
६.२५	०६-०६-२०१८
६.५०	०१-०८-२०१८
६.२५	०७-०२-२०१९

बैंक रेट बरकरार ६.५० फीसदी रहा

बैंक रेट : आंकड़ाकीय जानकारी

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

रेट (फीसदी)	तारीख
९.००	२९-०४-१९९८
८.००	०२-०३-१९९९
७.००	०२-०४-२०००
८.००	२२-०७-२०००
७.५०	१७-०२-२००१
७.००	०२-०३-२००१
६.५०	२३-१०-२००१
६.२५	३०-१०-२००२
६.००	२९-०४-२००३
९.५०	१३-०२-२०१२
९.००	१७-०४-२०१२
८.७५	२९-०१-२०१३
८.५०	१९-०३-२०१३
८.२५	०३-०५-२०१३
१०.२५	१५-०७-२०१३
९.५०	२०-०९-२०१३
९.००	०७-१०-२०१३
८.७५	२९-१०-२०१३
९.००	२८-०१-२०१४
८.७५	१५-०१-२०१५
८.५०	०४-०३-२०१५
८.२५	०२-०६-२०१५
६.७५	०४-१०-२०१६
६.५०	०६-०४-२०१७
६.२५	०२-०८-२०१७
६.५०	-------
६.७५	०१-०८-२०१८
६.५०	०७-०२-२०१९

सीआरआर फिलहाल में ४ फीसदी

2006 बाद से ष्टक्रक्र में किए बदलाव की तारीख

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

रेट (फीसदी)	तारीख
५.५०	०८-१२-२००६
५.७५	०७-०२-२००७
६.००	०३-०३-२००७
६.२५	१४-०४-२००७
६.५०	०८-०४-२००७
७.००	०४-०८-२००७
७.५०	०८-११-२००७
७.७५	२६-०४-२००८
८.००	१०-०५-२००८
८.२५	२४-०५-२००८
८.५०	०५-०७-२००८
८.७५	१९-०७-२००८
९.००	३०-०८-२००८
७.५०	११-१०-२००८
६.५०	१५-१०-२००८
६.००	०१-११-२००८
५.५०	०८-११-२००८
५.००	१७-०१-२००९
५.५०	१३-०२-२०१०
५.७५	२७-०२-२०१०
६.००	२४-०४-२०१०
५.५०	२८-०१-२०१२
४.७५	१०-०३-२०१२
४.५०	२२-०९-२०१२
४.२५	०३-११-२०१२
४.००	०९-०२-२०१३

तालिबान के समक्ष अमेरिका का समर्पण, चुनी हुई अफगानिस्तान सरकार पर छाए संकट के बादल

(जी.एन.एस.)अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत जालमे खलीलजाद ने कतर में तालिबान के साथ जो प्रस्तावित समझौता किया उसे ऐसे देखा जाना चाहिए मानो अमेरिका ने एक आतंकी संगठन के समक्ष समर्पण कर दिया है।असल में अमेरिकी इतिहास की सबसे लंबी लडाई पर विराम लगाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने व्यग्र हो चले हैं कि उन्हें कुछ भी मंजूर है। अफगानिस्तान में अमेरिका को फंसे हुए 17 साल से अधिक हो चले हैं। ऐसे में अमेरिका तालिबान के साथ जिस समझौते के प्रारूप पर सहमत हुआ है उसमें उसने दुश्मन की अधिकांश शर्तें मान ली हैं।तालिबान की सबसे बडी मांग यह थी कि अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से पूरी तरह वापस चली जाएं और उसे काबुल की सत्ता में साझेदारी भी मिले। इन मांगों पर भी अमेरिका ने मुहर लगा दी। बदले में इस आतंकी संगठन ने अमेरिका से एक तरह का फर्जी वादा ही किया कि वह अफगान धरती पर दूसरे आतंकी धडों को पैर नहीं जमाने देगा। हालांकि यह बात अलग है कि तालिबान को अफगानिस्तान में पहले से ही आइएसआइएस की तगडी चुनौती मिल रही है। इस 'प्रारूप' समझौते से हिंसा और भडकने की आशंका है जिससे चुनी हुई अफगान सरकार भी अस्थिर हो सकती है। तथाकथित 'शांति समझौता' एक तरह से अफगान महिलाओं पर

अत्याचार की तरह होगा, क्योंकि तालिबान उन पर वही मध्यकालीन कायदे थोपेगा जैसा उसने 1996–2001 के दौरान अपने निर्मम शासन में किया था। बीते कुछ वक्त में वहां महिलाओं और अन्य नागरिक अधिकारों के मोर्चे पर हुई प्रगति की स्थिति उलटने की आशंका बलवती हुई है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में जैसी शांति प्रक्रिया का वादा किया था उसके उलट उसने काबुल को भरोसे में लिए बगैर और उसके परामर्श के बिना ही तालिबान के साथ संभावित समझौता कर लिया। इसके बाद उसने अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी को इसके बारे में समझाने की कोशिश की जबकि गनी तालिबान को लेकर शंकालु रहे हैं और उन्होंने अमेरिका को आगाह भी किया कि वह तालिबान के समक्ष समर्पण की जल्दबाजी न दिखाए। इस प्रस्तावित करार में काबुल को तो अंधेरे में रखा ही गया, वाशिंगटन ने अपने 'प्रमुख रक्षा सहयोगी' भारत को भी भरोसे में लेने की जहमत नहीं उठाई। राष्ट्रपति पद संभालते ही ट्रंप ने वादा किया था कि वह अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए खराब हो रहे हालात को पलट देंगे, लेकिन दो साल बाद ही उन्हें हकीकत समझ आ गई कि वहां अमेरिका की नहीं, बल्कि इस्लामिक कट्टरपंथियों की ही जमीन मजबूत हो रही है। असल में ट्रंप उस काम को पूरा करना चाहते हैं जिसकी पहल उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा ने की थी, लेकिन वह अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। यह पहल थी तालिबान के साथ समझौता करने की। तालिबान के साथ सीधे वार्ता की सुविधा के लिए ओबामा ने इस लडाकू संगठन को कतर की राजधानी दोहा में कूटनीतिक मिशन शुरू करने की अनुमति भी दिला दी। साथ ही 2013 में पांच कट्टर तालिबानी लडाकों को ग्वांतेनामो बे जेल से रिहा भी किया। इसके पीछे अमेरिका की मंशा अपने एक सैनिक की रिहाई ही नहीं, बल्कि तालिबान के साथ वार्ता के लिए मंच तैयार करना था। तब तालिबान ने वार्ता के लिए अपने पांच साथियों की रिहाई को पूर्व निर्धारित शर्त बना दिया था। इन पांचों को अमेरिका के दिवंगत सीनेटर जॉन मैकेन ने 'कट्टरपंथियों में भी कट्टर' करार दिया था। अमेरिकी रुख में नरमी से तालिबान का हौसला और बडा है। हो सकता है कि वह अपनी आतंकी गतिविधियों को और ज्यादा धार दे। पूरे अफगानी समाज की तो छोडिए, तालिबान समूचे पश्तून समुदाय का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता। इनमें से अधिकांश पाकिस्तानी हैं जिन्हें पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी आइएसआइ ने ही प्रशिक्षित किया है। अमेरिकी रवैये में बदलाव से यही संदेश जा रहा कि वह अफगान युद्ध से आजिज आ चुका है और सम्मानजनक तरीके से विदाई के लिए बेसब्र है। इस पृष्ठभूमि में प्रस्तावित समझौता न केवल तालिबान के उभार पर मुहर लगाता है, बल्कि उसके संरक्षक पाकिस्तान के लिए भी एक बडी कूटनीतिक जीत है। पाकिस्तान ने ही इस समझौते में बिचौलिये की भूमिका निभाई है। पाकिस्तान पर अमेरिकी भरोसा घटता जा रहा है, ऐसी धारणा के उलट प्रस्तावित समझौता और उसे जल्द अंतिम रूप देकर लागू करने की अमेरिकी हडबडी यही दर्शाती है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तानी सेना और आइएसआइ की उपयोगिता बनी हुई है। इस तरह सीमा पार आतंकवाद को संरक्षण देने के बदले पाकिस्तान कूटनीतिक लाभ कमा रहा है। नैतिकता को ताक पर रखकर अमेरिका तालिबान के साथ जिस सौदेबाजी की दिशा में कदम बडा रहा है उससे उसका यह संदिग्ध रवैया भी जाहिर होता है कि लगातार आतंकी हमलों के बावजूद अमेरिका की विदेशी आतंकी संगठनों की सूची में तालिबान का नाम आखिर क्यों नहीं जोडा गया ? पाकिस्तान स्थित तालिबान के सीमा पार ठिकानों को निशाना बनाने को लेकर भी अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य मिशन के हाथ एक तरह से बांध दिए गए। इस तरह तालिबान को कुचलने के बजाय अमेरिका ने उसे फिर से खडा होने और अफगानियों को आतंकित करने का अवसर दे दिया। अमेरिका के लिए वक्त का पहिया घूमकर फिर वहीं आ गया है। अल कायदा की तरह तालिबान भी उन जिहादी समूहों में था जिन्हें सीआइए ने प्रशिक्षित कर 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्तेमाल किया था। समकालीन विश्व इतिहास में सबसे बडा आतंकी हमला झेलने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान और उसके प्रमुख आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का फैसला किया था, मगर अब अपनी सम्मानजनक विदाई के फेर में वह अफगानिस्तान को उन्हीं क्रूर हाथों में सौंपने के लिए तैयार है जिनके खिलाफ उसने 17 साल पहले जंग छे ?कर सत्ता से बेदखल किया था। ताजा घटनाक्रम भारत के लिए भी व्यापक निहितार्थ वाला है जिसके बारे में अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने कहा था कि उसने अपनी उदार मदद से अफगान लोगों के दिल में खास जगह बनाई है। पाकिस्तान तालिबान और अन्य आतंकी समूहों का समर्थक है जिन्हें वह अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है।

एमएसएफ रेट ६.५० फीसदी हुआ

एमएसएफ रेट.....

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

रेट (फीसदी)	तारीख
८.२५	०९-०५-२०११
८.५०	१६-०६-२०११
९.००	२६-०७-२०११
९.२५	१७-०९-२०११
९.५०	२५-१०-२०११
९.००	१७-०४-२०१२
८.७५	२९-०१-२०१३
८.५०	१९-०३-२०१३
८.२५	०३-०५-२०१३
१०.२५	१५-०७-२०१३
९.५०	२०-०९-२०१३
९.००	०७-१०-२०१३
८.७५	२९-१०-२०१३
९.००	२८-०१-२०१४
८.७५	१५-०१-२०१५
८.५०	०४-०३-२०१५
८.२५	०२-०६-२०१५
६.७५	०४-१०-२०१६
६.५०	०६-०४-२०१७
६.२५	०२-०८-२०१७
६.५०	-------
६.७५	०१-०८-२०१८
६.५०	०७-०२-२०१९

बजट के साथ-साथ.....

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

- सामान्य टैक्स में कोई वृद्धि नहीं
- वाटर और कोन्जर्वन्सी टैक्स में कोई वृद्धि नहीं
- वाहन टैक्स के दर में कोई वृद्धि नहीं
- वर्ष २०१९-२० के वर्ष के लिए कुल ८०५१ करोड़ का बजट
- शहर के विकास कार्यों के लिए ३९०३ करोड़ रुपये आवंटन
- स्टैंडिंग कमेटी के सुझाव से ५४२ करोड़ रुपये की वृद्धि
- इलेक्ट्रिक वाहनों को वाहन टैक्स में १०० फीसदी राहत
- एएमसी बिल्डिंग में स्थित ट्रस्ट -अस्पतालों के प्रॉपर्टी टैक्स में ७० फीसदी रिबेट
- चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालन किए जाते फीजियोथेरेपी सेंटर की प्रॉपर्टी टैक्स में भी ७० फीसदी रिबेट
- धार्मिक अवसर पर एस्टेट विभाग की फीस में माफी
- स्लम फ्री सीटी एक्शन प्लान-जीरो स्लम सीटी
- वाडज दांडीचौक में १० करोड़ रुपये के खर्च से फ्लाय ओवरब्रिज
- नरोडा पाटिया जंक्शन पर १० करोड़ रुपये के खर्च से फ्लाय ओवरब्रिज
- लालदरवाजा एएमटीएस बस टर्मिनस को हेरिटेज थीम के साथ डेवलप करने के लिए पांच करोड़ रुपये
- इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए १० करोड़ रुपये
- एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत लांभा-बलियादेव क्षेत्र डेवलपमेंट के लिए सात करोड़ रुपये
- करुणा अभियान और एनिमल अस्पताल के लिए ५ करोड़ रुपये
- गोता-गोधावी नहर के लिए दस करोड़ रुपये
- खारीकट नहर डेवलपमेंट योजना के लिए १० करोड़ रुपये
- शहर के छह मॉडल रोड के लिए ३० करोड़ रुपये
- गुजरात हाउसींग बोर्ड तथा स्लम क्लीयरन्स बोर्ड तथा औडा के आवासों में सुविधा के लिए १० करोड़ रुपये

रीपो रेट में ०.२५% की कटौती, जानें कैसे लें सस्ते लोन का फायदा

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई,

में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने रीपो रेट में कटौती करके लोगों को राहत दी है। इसे २५ बेसिस पॉइंट घटाकर ६.५% से ६.२५ कर दिया गया है। वहीं, नई मौद्रिक नीति के तहत रिवर्स रीपो रेट घटकर ६ प्रतिशत जबकि बैंक रेट ६.५० प्रतिशत पर आ गया है। इस कटौती से आम आदमी को भी फायदा होनेवाला है। रीपो रेट में कटौती के बाद नया लोन सस्ता होगा, लोन का टर्म कम हो सकता है जबकि कुछ असर जमा रकम के ब्याज पर भी पड़ेगा।

रीपो रेट क्या है ?

बैंकों को अपने दैनिक कामकाज के लिए प्राय: ऐसी बड़ी रकम की जरूरत होती है जिनकी मियाद एक दिन से ज्यादा नहीं होती। इसके लिए बैंक जो विकल्प अपनाते हैं, उनमें सबसे सामान्य है केंद्रीय बैंक (भारत में रिजर्व बैंक) से रात भर के लिए (ओवरनाइट) कर्ज लेना। इस कर्ज पर रिजर्व बैंक को उन्हें जो ब्याज देना पड़ता है, उसे ही रीपो दर कहते हैं।

रीपो रेट का यह असर

रीपो रेट कम होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है और इसलिए बैंक ब्याज दरों में कमी करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा रकम कर्ज के तौर पर दी जा सके। रीपो दर में कमी का सीधा मतलब यह होता है कि बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से रात भर के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा। साफ है कि बैंक दूसरों को कर्ज देने के लिए जो ब्याज दर तय करते हैं, वह भी उन्हें घटाना होगा।

बदलेगा MCLR, ग्राहकों को फायदा

ग्राहकों को नीतिगत ब्याज दर में कटौती का फायदा देने के लिए बैंकों में कर्ज देने का बीपीएलआर की जगह एमसीएलआर सिस्टम लागू किया है। मार्जिनल कॉस्ट पर आधारित लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर सिस्टम १ अप्रैल २०१६ से लागू है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एमसीएलआर की वकालत करते हुए कहा था कि बैंक बेस रेट के तहत ग्राहकों को नीतिगत ब्याज दर में कटौती का फायदा उतना नहीं देते जितना जितना देना चाहिए।

कैसे मिलेगा फायदा ?

बेस रेट और बीपीएलआर के तहत बैंक कर्ज की न्यूनतम दर तय करने के लिए अपना अपना तरीका इस्तेमाल करते थे, लेकिन एमसीएलआर सिस्टम के तहत सभी बैंकों को एक ही फार्म्युले के आधार पर लेंडिंग रेट तय करनी होती है। ऐसे में रीपो रेट घटने के कारण नया लोन सस्ता हो जाएगा। वैसे पहले ही लोन ले चुके लोगों की ईएमआई या रीपेमेंट पीरियड में कटौती की संभावना होती है, लेकिन रेट कट का फायदा उन्हें जरूर मिलता है जो बैंक से नया लोन लेने की सोच रहे हैं। अब उन्हें कम ब्याज दर पर बैंक से कर्ज मिल सकेगा।

आपने भी ले रखा है लोन तो...

अगर आपका किसी बैंक में पहले से लोन चल रहा है तो भी आपके पास रीपो रेट में कटौती का फायदा उठाने के रास्ते खुले हैं। इसके लिए आप किसी दूसरे बैंक में अपना लोन ट्रांसफर करवा सकते हैं। हालांकि, ऐसा करने से पहले पहले नए बैंक की ब्याज दर और लोन ट्रांसफर फी का पता कर लें क्योंकि हो सकता है कि लोन ट्रांसफर चार्ज पर ही इतना हो जिससे आपके पैसे बचाने का प्लान पर पानी फिर जाए। इसके अलावा आप अपने बैंक से संशोधित एमसीएलआर के मुताबिक लोन रीपेमेंट की व्यवस्था करने की मांग कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो आपका लोन पीरियड कम हो सकता है।

राहुल ने मोदी को चुनौती दी

मोदी को १० मिनट तक डिबेट करने की चुनौती

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का एक दूसरे पर वार-पलटवार का सिलसिला तेज होता जा रहा है। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नाटकीय अंदाज में हमला करते नजर आए। वाकया कांग्रेस के अल्पसंख्यक अधिवेशन का था। अधिवेशन में मौजूद कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल प्रधानमंत्री मोदी पर सवालों के जवाब से बचने का आरोप लगाते हुए नाटकीय अंदाज में माइक छोड़कर पीछे की ओर चलने लगे। राहुल ने कहा, वह बहुत डरपोक आदमी हैं। मैं उन्हें पहचान गया हूं। राहुल ने मोदी को १० मिनट तक अपने साथ डिबेट करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मोदी कभी डिबेट नहीं करेंगे, वह भाग जाएंगे। कांग्रेस के अल्पसंख्यक अधिवेशन में राहुल ने पीएम पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यह मैं किसी से भी कह देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को मेरे साथ एक स्टेज पर खड़ा कर दो। एक मंच पर १० मिनट के लिए डिबेट करवा दो। मैं कह रहा हूं यह डरता है। मैं इस आदमी को पहचान गया हूं, यह डरपोक आदमी है।

नई मौद्रिक नीति की प्रमुख बातें

(संपूर्ण समाचार सेवा)नई दिल्ली,

- मार्च तिमाही के लिए मुख्य मुद्रास्फीति (हेडलाइन इन्फ्लेशन) अनुमान को कम कर २.८ प्रतिशत किया गया।
- अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में मुद्रास्फीति ३.२ से ३.४ प्रतिशत तथा तीसरी तिमाही में ३.९ प्रतिशत रहने का अनुमान।
- जीडीपी वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में बढ़कर ७.४ प्रतिशत रहने का अनुमान जो २०१८-१९ में ७.२ प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष २०१९-२० में अप्रैल-सितंबर के दौरान वृद्धि दर ७.२ से ७.४ प्रतिशत तथा तीसरी तिमाही में ७.५ प्रतिशत रहने का अनुमान।
- कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर अस्पष्टता, ट्रेड टेंशन का वैश्विक वृद्धि संभावना पर होगा असर।
- केंद्रीय बजट प्रस्तावों से खर्च योग्य आय बढ़ेगी जिससे मांग को बढ़ावा मिलेगा।
- एक बार में थोक जमा परिभाषा को संशोधित किया गया। अब एक करोड़ रुपये के बजाए एक बार में २ करोड़ रुपये या इससे अधिक की जमा इस श्रेणी में आएगी।
- बड़ी श्रेणियों की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में तालमेल को लेकर दिशानिर्देश जारी किया जाएगा।
- रुपये के मूल्य में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी रुपया बाजार के लिए वर्कफोर्स गठित करने का प्रस्ताव।
- कंपनी बॉन्ड बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश पर पाबंदी हटी।
- भुगतान के लिए मंच उपलब्ध कराने की सेवा देने वाले तथा भुगतान संग्राहक के लिए परिचर्चा पत्र लाया जाएगा।
- बिना गारंटी के कृषि कर्ज देने की सीमा १ लाख रुपये से बढ़ाकर १.६० लाख रुपये की गई।
- इससे छोटे एवं सीमांत किसानों को मदद मिलेगी।
- कृषि कर्ज की समीक्षा के लिए कार्यकारी समूह का गठन।
- मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक २-४ अप्रैल को होगी।

स्वाइन फ्लू से मौत का आंकड़ा बढ़कर ५० हुआ

गुजरात में स्वाइन फ्लू का कहर : और ३ की मौत हुई

स्वाइन फ्लू से ग्रस्त मरिज अभी भी उपचार के तहत सिजनल फ्लु को रोकने के प्रयास फिरभी केस दर्ज हुए

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

गुजरात में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। आज स्वाइन फ्लू के कारण और तीन लोगों की मौत हो गई। भरूच, कच्छ और भावनगर में स्वाइन फ्लू से ग्रस्त एक-एक व्यक्ति की मौत होने से मौत का आंकड़ा बढ़र ५० पर पहुंच गया है। अभी भी ज्यादातर मरिज उपचार के तहत अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। नये साल में स्वाइन फ्लू के केस में उल्लेखनिय वृद्धि देखने को मिल रही है। १ जनवरी से लेकर बुधवार तक ३७ दिनों में मरीजों की संख्या ९०० से ऊपर पहुंच गई है। सिजनल फ्लु के कारण ज्यादातर मरिज सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालो में इलाज के तहत होने को जानना मिला है। वडोदरा, अहमदाबाद में स्वाइन फ्लू का आतंक दिख रहा है। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए तंत्र द्वारा अलग व्यवस्था की गई है। गत साल स्वाइन फ्लू के बड़ी संख्या में केस दर्ज हुए थे। तंत्र के द्वारा आंकड़े भी जारी किये गए थे। देश में स्वाइन फ्लू ग्रस्त सबसे ज्यादा आंकड़ा में गुजरात शामिल था। राजस्थान समेत राज्य में स्वाइन फ्लू के कारण खलबली मच गई थी। आज नये केस सतह पर आने से केसो की संख्या में वृद्धि ९६० के उपर पहुंच चुकी है। ३०० से ज्यादा उपचार के तहत होने का मालुम पडा है।

स्वाइन फ्लू का आतंक

(संपूर्ण समाचार सेवा)अहमदाबाद,

गुजरात में स्वाइन फ्लू का आतंक बढ़ रहा है। हररोज नये -नये लोग स्वाइन फ्लू के शिकजे में आ रहे है। आज तीन और लोगों की मौत से खलबली मच गई। नए वर्ष में स्वाइन फ्लू का चित्र नीचे के अनुसार है।

स्वाइन फ्लू के कुल केस	९६० से ज्यादा
स्वाइन फ्लू से मौत	५० से ज्यादा
उपचार के तहत लोग	३०० से ज्यादा
स्वस्थ हुए लोग	४४४ से ज्यादा
२४ कलाक में मौत	०३

ईडी की एक टीम वाड्रा का बयान दर्ज कर रही है

मनी लॉन्ड्रिग केस : ईडी दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई

वाड्रा के साथ उनकी पत्नी प्रियंका भी पहुंचीं : पूछताछ करने वाली टीम में ईडी के जॉइंट डायरेक्टर, डेप्युटी डायरेक्टर और ५ अन्य अधिकारी शामिल

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

मनी लॉन्ड्रिग केस के सिलसिले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ चल रही है। इससे पहले, वाड्रा के साथ उनकी पत्नी प्रियंका वाड्रा भी ईडी दफ्तर पहुंचीं, हालांकि वह गेट से ही लौट गईं। ईडी की एक टीम वाड्रा का बयान दर्ज कर रही है। वहीं, प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि वह अपने पति के साथ हैं। वाड्रा से पूछताछ करने वाली टीम में ईडी के जॉइंट डायरेक्टर, डेप्युटी डायरेक्टर और ५ अन्य अधिकारी शामिल हैं। बता दें कि शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर मनी लॉन्ड्रिग केस में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर १६ फरवरी तक के लिए रोक लगा दी थी। अदालत ने वाड्रा को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए ईडी को उनसे ६ फरवरी को पूछताछ की इजाजत दी थी। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा विदेश में कथित तौर पर अवैध संपत्ति रखने के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिग से जुड़े एक मामले में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। वाड्रा की पत्नी प्रियंका वाड्रा सफेद टोयोटा लैंड कूजर गाड़ी में उनके साथ थीं और उनके पीछे एसपीजी के सुरक्षाकर्मियों की गाड़ियां थीं। उन्होंने वाड्रा को मध्य दिल्ली के जामनगर हाउस स्थित एजेंसी के दफ्तर के सामने छोड़ा और वहां से फौरन अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना हो गईं। अपने पति से ईडी की पूछताछ के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका ने कहा कि वह अपने परिवार के साथ खड़ी हैं। वाड्रा करीब ३ बजकर ४७ मिनट पर ईडी के दफ्तर में दाखिल हुए। उनके वकीलों का एक दल पहले ही वहां पहुंच चुका था। यह पहला मौका है जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा वाड्रा संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के आपराधिक आरोपों के सिलसिले में किसी जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुए हैं। वाड्रा ने पहले इन आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि राजनीतिक बदले के लिये उनके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली की एक अदालत ने वाड्रा को केंद्रीय जांच एजेंसी से सहयोग करने को कहा था। वाड्रा ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने उनसे विदेश से लौटने के बाद बुधवार को ईडी के समक्ष पेश होने के कहा था। मनी लॉन्ड्रिग का यह केस लंदन स्थित एक प्रॉपर्टी की खरीदारी से जुड़ा है। वाड्रा के करीबी सहयोगी कहे जाने वाले सुनील अरोड़ा के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिग का केस दर्ज किया है। इस मामले में अरोड़ा को कोर्ट से १६ फरवरी तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल चुकी है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा विदेश में कथित तौर पर अवैध संपत्ति रखने के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिग से जुड़े एक मामले में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। वाड्रा की पत्नी प्रियंका वाड्रा सफेद टोयोटा लैंड कूजर गाड़ी में उनके साथ थीं और उनके पीछे एसपीजी के सुरक्षाकर्मियों की गाड़ियां थीं। उन्होंने वाड्रा को मध्य दिल्ली के जामनगर हाउस स्थित एजेंसी के दफ्तर के सामने छोड़ा और वहां से फौरन अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना हो गईं। अपने पति से ईडी की पूछताछ के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका ने कहा कि वह अपने परिवार के साथ खड़ी हैं। वाड्रा करीब ३ बजकर ४७ मिनट पर ईडी के दफ्तर में दाखिल हुए। उनके वकीलों का एक दल पहले ही वहां पहुंच चुका था। यह पहला मौका है जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा वाड्रा संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के आपराधिक आरोपों के सिलसिले में किसी जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुए हैं।यह मामला लंदन के १२, ब्रायनस्टन स्क्वेयर स्थित १९ लाख पाउंड (करीब १७ करोड़ रुपये) की एक प्रॉपर्टी की खरीदारी में कथित मनी लॉन्ड्रिग से जुड़ा हुआ है। ईडी का दावा है कि इस संपत्ति के असल मालिक रॉबर्ट वाड्रा हैं। कोर्ट में ईडी ने यह भी दावा किया कि वाड्रा और उनके सहयोगियों को २००९ में हुई पेट्रोलियम डील में भी पैसे मिले थे। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि लंदन स्थित फ्लैट को भगोड़े डिफेंस डीलर संजय भंडारी ने १६ करोड़ ८० लाख रुपये में खरीदा था।

सलमान फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी

एक बार फिर से जासूस के रोल में दिखेंगे सलमान खान

सलमान को साउथ कोरियन सुपरहिट फिल्म वेटरन ऑफर की गई है जिसमें जासूस का रोल निभाना होगा

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई,

बॉलिवुड सुपरस्टार सलमान खान इस समय अपनी आने वाली फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन अली अब्बास जफर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सलमान को एक और फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है जिसमें उन्हें जासूस का रोल निभाना है। यह फिल्म एक कोरियन फिल्म की रीमेक होगी। रिपोर्टस के मुताबिक सलमान खान को साउथ कोरियन सुपरहिट फिल्म वेटरन ऑफर की गई है जिसमें उन्हें जासूस का रोल निभाना होगा। इस फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए रील लाइफ प्रॉडक्शन ने राइट्स हासिल किए हैं। वेटरन को रू सियंग-वांग ने डायरेक्ट किया था और इसमें ह्यांग जुंग मिन ने एक वेटरन कॉप की भूमिका निभाई थी। बता दें कि सलमान की असली फिल्म भारत में उनके साथ कटरीना कैफ, तब्बू, दिशा पाटनी, जेकी श्रॉफ और सुनील ग्रोवर दिखाई देंगे। यह फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। हाल में इसका टीजर रिलीज किया गया था जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था।

सामाजिक सेवा करने की विस्मय ने विश्वास दिलाया

शराब की मेहफिल : विस्मय को शर्त के तहत जमानत मंजूर

फार्म हाउस पर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अन्य ५ के साथ विस्मय शराब की मेहफिल में गिरफ्तार हुआ था

(संपूर्ण समाचार सेवा)

अहमदाबाद,६ फरवरी।

गुजरात हाईकोर्ट ने शराब की मेहफिल के संदर्भ में विस्मय शाह को बुधवार को जमानत दे दी। विस्मय शाह पहले वस्त्रापुर हिट एंड रन केस में भी अपराधी ठहराया गया था। अडालज में फार्म हाउस पर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शराब की मेहफिल का मजा लेने के मामले में विस्मय शाह की अन्य पांच के साथ गिरफ्तार किया गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को पूरे मामले में विस्मय की जमानत अर्जी पर दलीलें की सुनवाई पूरी की थी और फैसले की तारीख ६ फरवरी निश्चित की गई थी। दोनों पक्षों की तरफ से तार्किक दलीलें दी गई थी। इस केस में सुनवाई करने के बाद जस्टिस एवाय कोग्जे द्वारा फैसले की तारीख ६ फरवरी पर छोड़ी थी। विस्मय शाह ने सामाजिक सेवा करने की गारंटी देने के बाद पूरे मामले में विस्मय को जमानत मिल गई। इसके पहले जस्टिस उमेश त्रिवेदी, एपी ठाकर और वीवी मायाणी के समक्ष विस्मय की जमानत अर्जी की सुनवाई होने वाली थी लेकिन यहां मामला आगे नहीं बढ़ा। जस्टिस ने खुद को अलग कर लेने से इसकी चर्चा देखने को मिली। ४ जनवरी को जस्टिस एसी राव ने विस्मय इसकी पत्नी पूजा और यह कपल के चार मित्र को अस्थायी जमानत दी गई। अडालज में फार्म हाउस पर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शराब की मेहफिल का मजा लेने के मामले में विस्मय शाह की अन्य पांच के साथ गिरफ्तार किया गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को पूरे मामले में विस्मय की जमानत अर्जी पर दलीलों की सुनवाई पूरी की थी और फैसले की तारीख ६ फरवरी निश्चित की गई थी। दोनों पक्षों की तरफ से तार्किक दलीलें दी गई थी। जस्टिस कोग्जे ने पांच आरोपियों को नियमित जमानत मंजूर किए थे लेकिन विस्मय के पहले व्यवहार की जानकारी मांगी थी।वस्त्रापुर क्षेत्र में २०१३ में दो युवकों ने हिट एंड रन मामले में मौत हुई थी। विस्मय ने बुधवार को सामाजिक सेवा करने का विश्वास दिलाया जिसकी वजह से विस्मय को जमानत मिल गई। हालांकि इसके व्यवहार को सुधार करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। गुजरात में शराबबंदी होने से विस्मय के मामले में सख्त रवैया अपनाया गया था। कानून गरीब और अमीर के बीच अलग-अलग तरीके से नहीं होना चाहिए ऐसी दलील दी गई थी। शराबबंदी के कानून भंग करने पर आरोपी के विरूद्ध पहली बार अपराध दर्ज होने की दलील दी गई थी।

स्टैंडिंग कमेटी के सुझाव के अनुसार शहर के विकास कार्य

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

फ्लाय ऑवरब्रिज	रुपये ३० करोड़
लालदरवाजा टर्मिनस डेवलपमेन्ट	रुपये ५ करोड़
माणेकचौक रिडेवलपमेन्ट प्लान और हेरीटेज स्ट्रीट	रुपये ५ करोड़
इन्टर मॉडल ट्रान्सपोर्ट हब	रुपये १० करोड़
लांभा बलियादेव मंदिर क्षेत्र डेवलपमेन्ट	रुपये ७ करोड़
माइक्रोलिंग पद्धति से ड्रेनेज लाइन	रुपये १० करोड़
नये पश्चिम क्षेत्र में स्ट्रोमवोटर नेटवर्क	रुपये १० करोड़
खारीकट केनाल पार्ट डेवलपमेन्ट	रुपये १० करोड़
मोडल रोड डेवलपमेन्ट	रुपये ३० करोड़
होटमीक्ष प्लान्ट पश्चिम क्षेत्र	रुपये १० करोड़
वेजिटेबल मार्केट तथा मार्केट नवीनीकरण	रुपये ३ करोड़
पुरानी सीमा के गामतल विकास	रुपये ३ करोड़
स्ट्रीटलाइट पोल आधारित एड्रेस सिस्टम	रुपये १ करोड़
हाउसींग बोर्ड के आवास में सुविधा	रुपये १० करोड़
एनिमल होस्टेल	रुपये ५ करोड़
आंगनवाडी मकान-स्मार्ट आंगनवाडी	रुपये ३ करोड
अर्बन फोरेस्ट	रुपये १ करोड
थीम बेइज गार्डन	रुपये ३ करोड
प्रेमाभाई होल पुन: कार्य करने	रुपये ३ करोड
ओडिटोरियम, कोम्युनिटी हॉल, पार्टी प्लोट	रुपये १० करोड
स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्ष, पूर्व क्षेत्र	रुपये ५ करोड
क्रिकेट कोचींग स्पोर्टस कॉम्पलेक्ष, हेल्थ क्लब	रुपये ६ करोड
रीडींग लायब्रेरी	रुपये २ करोड
१००० बेड रेफरल अस्पताल-पूर्व	रुपये ७ करोड
शारदाबेन अस्पताल नवीनीकरण	रुपये १० करोड
एलजी अस्पताल-सुपर स्पेश्यालिटी सेवा	रुपये २ करोड
सुविधायुक्त स्मशानगृह	रुपये १० करोड
एस्केलेटर के साथ फुट ओवरब्रिज	रुपये २ करोड
म्यु.काउन्सीलर-म्यु. अधिकारी क्लब हाउस	रुपये १ करोड

शासक पक्ष भाजपा द्वारा ५४२ करोड़ की वृद्धि के सुझाव के साथ

एएमसी द्वारा २०१९-२० के लिए ८०५१ करोड़ रुपये का बजट मंजूर

लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर चुनाव संबंधी घोषणा का बजट विकास के कार्यों के लिए ४१२३ करोड़ रुपये आवंटन कराया गया

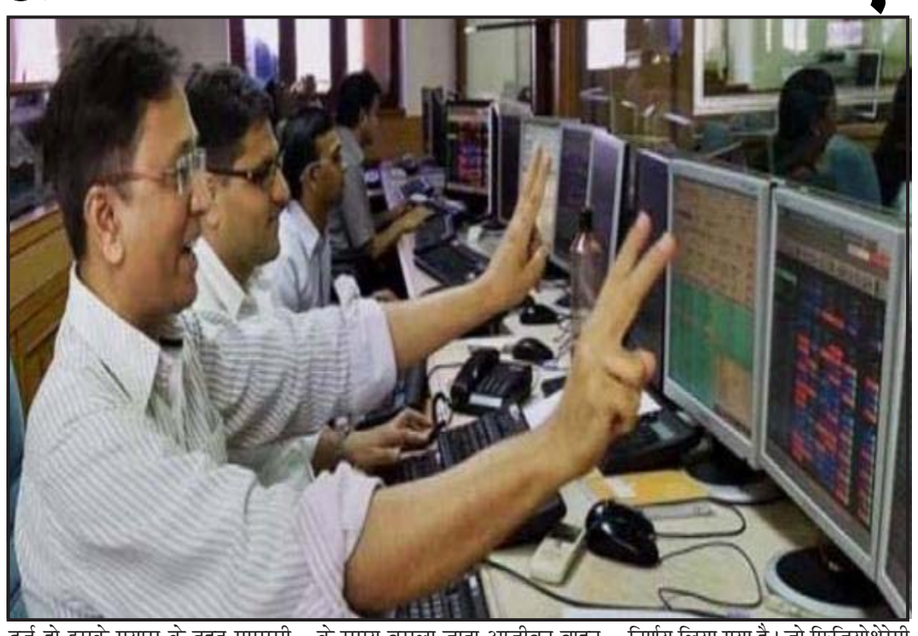

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिशनर विजय नेहरा द्वारा पहले पेश किए गए कुल ७५०९ करोड़ रुपये के ड्राफ्ट बजट में शासक पक्ष भाजपा द्वारा ५४२ करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ वर्ष २०१९-२० के लिए कुल ८०५१ करोड़ रुपये का बजट बुधवार हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में मंजूर किया गया। जिसमें राजस्व खर्च में ३२२ करोड़ रुपये और विकास के कार्यों में २२० करोड़ रुपये मिलाकर कुल ५४२ करोड़ रुपये की वृद्धि का सुझाव दिया गया है। म्युनिसिपल कमिशनर द्वारा पेश किया गया। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर शासक पक्ष द्वारा फिर एक बार विकास के कार्यों की बड़ी और चुनाव संबंधी घोषणाएं की गई है । जिसमें विकास के कार्यों के लिए ४१२३ करोड़ रुपये आवंटन कराया गया है। सामान्य टैक्स में, वॉटर और कंजर्वन्सी टैक्स या वाहन टैक्स में किसी भी प्रकार की वृद्धि बिना का बजट बुधवार को मंजूर किया गया। एएमसी प्रशासन का वर्ष २०१९-२० के बजट मामले में जानकारी देते हुए बीजलबहन पटेल और स्टेन्डिंग कमिटी के चेयरमैन अमूल भट्ट ने बताया कि, शहर में प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज हो इसके प्रयास के तहत एएमसी प्रशासन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़े और कार्बन की मात्रा में कमी दर्ज हो तथा एयरक्वॉलिटी में सुधार हो इस उद्देश्य से २०१९-२० के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों के आरटीओ पासींग के समय वसूला जाता आजीवन वाहन टैक्स में १०० फीसदी की बड़ी राहत देने का तय किया गया है । इसी प्रकार से चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालन किया जाता फिजियोथेरेपी सेन्टर की प्रॉपर्टी टैक्स में ७० फीसदी रिबेट देने का महत्व का निर्णय लिया गया है। जो फिजियोथेरेपी सेन्टर पब्लिक रजिस्टर्ड चेरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ द्वारा पब्लिक चेरिटेबल हेतु के लिए चलाया जाता हो और जो गरीबों और सामान्य नागरिकों को फिजियोथेरेपी उपचार मामूली कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हो ऐसी संस्थाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में ७० फीसदी रिबेट का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से संस्थानों पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड हुए हो और जो गरीब तथा आम वर्ग के लोगों को मामूली कीमत पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराते हो और कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग का यह सेवाओं के लिए उपयोग कर रही हो ऐसी संस्था को २०१९-२० के वर्ष से प्रॉपर्टी टैक्स में ७० फीसदी रिबेट देने का ठहरा गया है। इसके अलावा पहली बार शहर में निजी मालिकी की जमीन में धार्मिक संबोधन-कथा जैसे कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर मंडप खड़ा करने के लिए एस्टेट विभाग द्वारा लिया जाता मंडप की फीस में संबोधन-कथा जैसे कार्यक्रम को माफी देने का ठहरा गया है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर शासक पक्ष द्वारा फिर एक बार विकास के कार्यों की बड़ी और चुनाव संबंधी घोषणाएं की गई है । जिसमें विकास के कार्यों के लिए ४१२३ करोड़ रुपये आवंटन कराया गया है । सामान्य टैक्स में, वॉटर और कंजर्वन्सी टैक्स या वाहन टैक्स में किसी भी प्रकार की वृद्धि बिना का बजट बुधवार को मंजूर किया गया । एएमसी प्रशासन का वर्ष २०१९-२० के बजट मामले में जानकारी देते हुए बीजलबहन पटेल और स्टेन्डिंग कमिटी के चेयरमैन अमूल भट्ट ने बताया कि, शहर में प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज हो इसके प्रयास के तहत एएमसी प्रशासन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़े और कार्बन की मात्रा में कमी दर्ज हो तथा एयरक्वॉलिटी में सुधार हो इस उद्देश्य से २०१९-२० के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों के आरटीओ पासींग के समय वसूला जाता आजीवन वाहन टैक्स में १०० फीसदी की बड़ी राहत देने का तय किया गया है । इसी प्रकार से चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालन किया जाता फिजियोथेरेपी सेन्टर की प्रॉपर्टी टैक्स में ७० फीसदी रिबेट देने का महत्व का निर्णय लिया गया है। जो फिजियोथेरेपी सेन्टर पब्लिक रजिस्टर्ड चेरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ द्वारा पब्लिक चेरिटेबल हेतु के लिए चलाया जाता लोकसभा चुनाव को ध्यान में लेकर शहर में जिन विकास कार्यों की घोषणा की गई है, इसमें वाडज दांडी चौक में ३० करोड़ रुपये के खर्च से फ्लाय ओवरब्रिज, नरोडा पाटिया फ्लाय ओवरब्रिज, मणिनगर रेलवे क्रासिंग रेलवे ओवरब्रिज, शाहीबाग डफनाला फ्लाय ओवरब्रिज, नरोडा सिनेमा गेलेक्षी सिनेमा फ्लाय ओवरब्रिज, विनोबानगर तथा विवेकानंदनगर को जोड़ता लो-लेवलब्रिज के विकास काम का आयोजन किया गया है । इसके अलावा, लालदरवाजा, एएमटीएस बस टर्मिनस को हेरिटेज थीम के साथ डेवलप करने के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान, माणेकचौक रिडेवलपमेन्ट प्लान क्लीन हेरिटेज स्ट्रीटफूड हब के लिए ५ करोड़ रुपये, इंडर मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए १० करोड़ रुपये, एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत लांभा-बलियादेव मंदिर क्षेत्र डेवलपमेंट, लांभा क्षेत्र के १० गामतल, विकास हेल्थक्लब, पुस्तकालय, करुणा अभियान और एनिमल अस्पताल के लिए ५ करोड़ रुपये, पूर्व क्षेत्र में माइक्रोलींक पद्धति से सुएजमेइन ट्रन्क लाइन, पूर्व में औद्योगिक गृह के साथ संकलन करके रिसायकल वाटर के उपयोग के लिए १० करोड़ रुपये, गोता-गोधावी नहर के लिए दस करोड़ रुपये, खारीकट नहर डेवलपमेंट योजना के लिए १० करोड़ रुपये, शहर के छह मॉडल रोड के लिए ३० करोड़ रुपये, गुजरात हाउसींग बोर्ड तथा स्लम क्लीयरन्स बोर्ड तथा औडा के आवासों में सुविधा के लिए १० करोड़ रुपये, कांकरिया ओपनएयर थियेटर में ओडिटोरियम, पूर्व क्षेत्र में बंद मिल की कटौती जगह में कॉम्युनिटी हॉल, डॉ. बाबासाहब आंबेडकर कॉम्युनिटी हॉल, वासणा कॉम्युनिटी हॉल, वातानुकूलित नरोडा कॉम्युनिटी हॉल नवीनीकरण, शारदाबहन अस्पताल के नवीनीकरण के लिए १० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सफल ऑपरेशन

बीजापुर में सुरक्षाबलों को सफलता, १० नक्सली ढेर

बीजापुर में हुए इस ऑपरेशन को स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गाड्र्स ने मिलकर अंजाम दिया

(संपूर्ण समाचार सेवा) बीजापुर,

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां गुरुवार को १० नक्सलियों को खत्म कर दिया गया। इस ऑपरेशन को स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गाड्र्स ने मिलकर अंजाम दिया। सुरक्षाबलों ने नक्सलिउन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी अभियान अभी जारी है। नक्सलियों के पास से ११ हथियार भी बरामद किए। यह जानकारी बीजापुर के एसपी मोहित गर्ग ने दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह करीब ११ बजे भैरामगढ़ थान क्षेत्र के जंगल वाले इलाके में STF और DRG ने मिलकर १० नक्सलियों को ढेर कर दिया। उनके पास से ११ हथियार बरामद हुए हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी अभियान अभी जारी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के ही सुकमा जिले में शनिवार को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला की जान चली गई थी। सुकमा के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बताया था कि गोदेलगुडा गांव निवासी महिला किसी दैनिक कार्य के लिए जंगल गई थी और उसी दौरान वह सुरक्षाबलों और उग्रवादियों के बीच हो रही गोलीबारी की चपेट में आ गई। उनके साथ गईं एक अन्य महिला घायल हो गई थीं। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस का एक दल इलाके में अभियान चलाने के बाद लौट रहा था। उसी दौरान आम नागरिकों की तरह दिखने वाले ६-७ नक्सलियों ने रेंगईगुड़ा इलाके में उन पर गोलीबारी शुरू कर दी।

स्टीव स्मिथ पर सर्जरी रही सफल

वर्ल्डकप में हो सकती है स्टीव स्मिथ की एंट्री

(संपूर्ण समाचार सेवा) सिडनी,

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में शामिल हो सकते हैं। दरअसल वह लिगामेंट की समस्या से जूझ रहे थे जिस वजह से उन्हें बांग्लादेश प्रीमियर लीग टी२० टूर्नमेंट से भी बाहर होना पड़ा था। दिक्कत से निजात पाने के लिए उन्होंने सर्जरी करवाई जो सफल रही। उनके मैनेजमेंट का कहना है कि वह वर्ल्ड कप खेलने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्मिथ के मैनेजर बारेन क्रेग ने कहा कि सर्जरी ठीक-ठाक रही और उन्हें खेलने के लिए तैयार होने में अभी साढ़े तीन हफ्ते का समय लगेगा। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि वह इंडियन प्रीमियर लीग में खेले और इसके बाद वर्ल्ड कप और फिर एशेज में भी खेले। बता दें स्मिथ पर गेंद से छेड़छाड़ के लिए लगा बैन भी मार्च के अंत में खत्म हो रहा है।

दोनों को क्रिकेट का आनंद उठाना चाहिए : सचिन

पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल में काबिलियत : सचिन तेंडुलकर

सचिन तेंडुलकर ने उम्मीद जताई कि टीम इंडिया २०११ की तरह इस बार भी वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब होगी

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

महान क्रिकेटरों में शुमार सचिन तेंडुलकर का मानना है कि युवा पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल में काफी क्षमता है और उन्हें क्रिकेट का आनंद उठाना चाहिए। सचिन ने साथ ही उम्मीद जताई कि टीम इंडिया २०११ की तरह इस बार भी वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब होगी। पृथ्वी ने पिछले साल वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से इंटरनैशनल क्रिकेट में डेब्यू किया तो वहीं, शुभमन को न्यू जीलैंड के खिलाफ हाल में संपन्न वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कैप दी गई। दोनों ही १९ साल के हैं। १६ साल की उम्र में इंटरनैशनल डेब्यू करने वाले सचिन ने बताया कि वह पहले से जानते थे कि पृथ्वी भारत के लिए जरूर खेलेंगे। उन्होंने कहा, मैंने पृथ्वी से पहले ही बात की थी। जब वह ८-९ साल के थे, तब मैंने उन्हें नेट्स पर अभ्यास करते देखा। वह मुझे कुछ खास लगे। मुझे तब ही लगा कि वह जरूर टीम इंडिया से खेलेंगे। पृथ्वी ने अक्टूबर २०१८ में पहला टेस्ट मैच खेला। वहीं, शुभमन ने न्यू जीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में डेब्यू किया जो भारतीय टीम ने ४-१ से जीती। दोनों ही क्रिकेटर पिछले साल अंडर-१९ वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, जब भारत ने न्यू जीलैंड में खिताबी जीत दर्ज की। पृथ्वी उस टीम के कप्तान थे और उन्होंने ५ पारियों में २६१ रन बनाए। शुभमन ने१ शतक और ३ अर्धशतक जड़े जिसके दम पर मैन ऑफ द सीरीज चुने गए। ४५ वर्षीय सचिन ने कहा, 'शुभमन ने पिछले साल अंडर-१९ वर्ल्ड कप में अहम भूमिका अदा की और उनका घरेलू सीजन भी काफी अच्छा रहा। मुझे लगता है कि दोनों (पृथ्वी और शुभमन) में काफी क्षमता है। उन्होंने अभी टीम इंडिया के ळए खेलना शुरू किया है और दोनों को क्रिकेट का आनंद उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि २०११ में वर्ल्ड कप जीत उनका इस टूर्नमेंट से जुड़ा सबसे खास पल है। सचिन ने कहा, मैंने १९८३ वर्ल्ड कप जीत देखी जिसकी हर किसी ने खुशी मनाई। सपना देखा और घरेलू सरजमीं पर २०११ में वर्ल्ड कप जीतना सबसे खास रहा। २०१९ वर्ल्ड कप में अब कुछ महीने ही बचे हैं। सचिन को उम्मीद है कि मौजूदा भारतीय टीम वह कर सकती है जो ८ साल पहले २०११ में उनके टीम साथियों ने किया।

पोरबंदर या अमरेली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं

लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं हार्दिक पटेल

हमें अभी तक हार्दिक पटेल से कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं मिला है : गुजरात कांग्रेस के चीफ अमित चावड़ा

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने इस साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ यह अटकलें भी तेज हो गई हैं कि वह पोरबंदर या अमरेली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यह दोनों ही लोकसभा सीटें पाटीदार बहुल हैं। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि वह जिग्नेश मेवाणी की तरह ही कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि मेवाणी ने वर्ष २०१७ में हुआ विधानसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। पिछले साल जुलाई महीने में हार्दिक २५ साल के हो गए। वह अब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो गए हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जहां से हार्दिक पटेल चुनाव लड़ेंगे, वहां कोई प्रत्याशी न उतारा जाए। इससे हमें पूरे राज्य में पाटीदार वोट मिलेंगे। हालांकि हमें अपने स्थानीय नेताओं को पार्टी के लिए हार्दिक पटेल की उम्मीदवारी के महत्व को बताना होगा। कांग्रेस नेता ने कहा, हम समझते हैं कि पोरबंदर और अमरेली से हार्दिक पटेल आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अमरेली सीट से हार्दिक चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि उन्हें स्थानीय विधायकों की अच्छी छवि को भुनाना होगा। उन्हें सूरत से भी मदद मिल सकती है जहां बड़ी संख्या में अमरेली के लोग रहते हैं। इस बीच कई दिग्गजों की नजर अमरेली सीट पर है, इसलिए इस बात की बेहद कम संभावना है कि हार्दिक अमरेली से चुनाव लड़ें। इसके विपरीत हार्दिक के पोरबंदर से चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा है जहां ७ विधानसभा सीटों में से दो पर कांग्रेस का कब्जा है। यहां एक सीट पर एनसीपी उम्मीदवार को जीत मिली है। एनसीपी विधायक भी हार्दिक की मदद कर सकता है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जहां से हार्दिक पटेल चुनाव लड़ेंगे, वहां कोई प्रत्याशी न उतारा जाए। इससे हमें पूरे राज्य में पाटीदार वोट मिलेंगे। हालांकि हमें अपने स्थानीय नेताओं को पार्टी के लिए हार्दिक पटेल की उम्मीदवारी के महत्व को बताना होगा। कांग्रेस नेता ने कहा, हम समझते हैं कि पोरबंदर और अमरेली से हार्दिक पटेल आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अमरेली सीट से हार्दिक चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि उन्हें स्थानीय विधायकों की अच्छी छवि को भुनाना होगा ।उधर, गुजरात कांग्रेस के चीफ अमित चावड़ा कहते हैं, हमें अभी तक हार्दिक पटेल से कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। जब हमें यह मिल जाएगा तो हम इस पर फैसला करेंगे। इस संबंध में हार्दिक पटेल से संपर्क नहीं हो पाया।

छह मॉडल रोड के लिए ३० करोड़ का प्रावधान

३० करोड़ रुपये के खर्च से छह फ्लाय ओवरब्रिज बनेंगे

दांडी चौक पर फ्लाय ओवरब्रिज तैयार करने का आयोजन

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

एएमसी प्रशासन द्वारा मंजूर किए गए वर्ष २०१९-२० के बजट में मेयर बीजलबहन पटेल और स्टेन्डिंग कमिटी के चेयरमैन अमूल भट्ट द्वारा महत्व के विकास कार्यों की घोषणा की गई थी। शहर में ३० करोड़ रुपये के खर्च से छह फ्लाय ओवरब्रिज बनाये जायेंगे। जिसमें वाडज दांडी चौक, नरोडा पाटिया, मणिनगर रेलवे क्रासिंग, शाहीबाग डफनाला, नरोडा गेलेक्षी सिनेमा और विनोबानगर -विवेकानंदनगर को जोड़ता लो-लेवल ब्रिज भी शामिल है। शहर में ट्राफिक की समस्या समाधान करने के तहत फिलहाल अहमदाबाद शहर में अंजली चार रास्ता, फ्लायओवर, इन्कमटैक्स चार रास्ता, विराटनगर जंक्शन अजीतमिल जंक्शन, नरोडा रेलवे क्रासिंग, सीम्स अस्पताल, राजेन्द्रपार्क जंक्शन फ्लायओवर तथा खोखरा अनुपम रेलवे ओवरब्रिज वाइडनींग का काम किया जा रहा है।

इसी तरीके से जगतपुर रेलवे क्रासिंग तथा चांदलोडिया, राणिप नए राणिपब्रिज के नीचे अंडरब्रिज, घोडासर स्मृतिमंदिर जंक्शन पर फ्लायओवर, पालडी जंक्शन, नारणपुरा पल्लव चार रास्ता, सत्ताधार चार रास्ता फ्लायओवर के कामकाज आयोजन में है। इसके अलावा नये आयोजन में दांडी चौक पर फ्लाय ओवरब्रिज तैयार करने का आयोजन है जिसकी वजह से गांधीनगर तथा नए वाडज की तरफ जाता ट्राफिक नोन स्टोप ट्राफिक हो सकता है, इसे ध्यान में लेकर इस बजट में दांडी चौक पर फ्लाय ओवरब्रिज के लिए १० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शहर के पूर्व क्षेत्र में नरोडा पाटिया जंक्शन की ट्राफिक समस्या को आसान करने के लिए नरोडा पाटिया जंक्शन पर भी फ्लायओवरब्रिज बनाने के लिए १० करोड़ रुपये आवंटन कराया गया है। शहर में ७६ किलोमीटर के रिंगरोड के आसपास एफोर्डेबल हाउसींग के प्रॉजेक्ट हो रहे है, जिसकी वजह से पूर्व तरफ के क्षेत्र की बड़ी कॉलोनियों के साथ यह क्षेत्र जुड़ रहा है। पूर्व क्षेत्र में विनोबाभावे नगर और विवेकानंद नगर के आवास के बीच खारी नदी का हिस्सा स्थित है।

गुजरात कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

गुजरात में २४ घंटे रिटेल बाजारों को खुला रखने का निर्णय

बैठक में निर्णय लेने के बाद खानेपीने से लेकर अन्य सभी कारोबारियों को लाभ : रोजगार बढ़ने की संभावना

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

गुजरात में रिटेल बाजार को २४ घंटे खुला रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है । जिसकी वजह से कारोबारियों को बड़ी राहत और प्रोत्साहन मिलेगा । खानेपीने से लेकर अन्य कारोबारियों को सीधा लाभ मिलेगा। उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने कैबिनेट की बैठक के बाद लिए गए निर्णय मामले में जानकारी दी। सर्विस वर्ग को भी इसकी वजह से लाभ होगा। रात के समय में नौकरी करते लोगों को सीधा राहत होगा । पिछले कई दिनों से २४ घंटे खुदरा बाजार को खुला रखने को लेकर चर्चा हो रही थी। कारोबारियों की तरफ से इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। वर्तमान में रात के १२ बजे तक व्यापार-धंधा किया जा सकता था। लेकिन नये संशोधन की वजह से २४ घंटे दुकानें खुली रख सकते है। इसके साथ सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है कि दुकानें २४ घंटे चालू रहने से रोजगार बढ़ेगा। कैबिनेट की बैठक में श्रम और रोजगार विभाग द्वारा कानून में संशोधन करके मंजूर किया गया। खानेपीने से लेकर अन्य कारोबारियों को सीधा लाभ मिलेगा। उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने कैबिनेट की बैठक के बाद लिए गए निर्णय मामले में जानकारी दी। सर्विस वर्ग को भी इसकी वजह से लाभ होगा। ठंड के सिजन में १८ तारीख को शॉप एस्टेबलिशमेन्ट ऐक्ट में संशोधन प्रदर्शित करता बिल पेश किया जाएगा। राज्य में करीब ७ लाख दुकानदार रजिस्टर्ड है। उनको अनिवार्य रूप से हर वर्ष रजिस्ट्रेशन कराना होता था। लेकिन यह बिल को लाने का निर्णय लिए जाने पर व्यापारियों को रिन्यू कराने से मुक्ति मिलेगी। नए व्यापारी अब सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। व्यापारियों द्वारा २४ घंटे दुकानें चालू रखने से ओवर टाइम करने वाले को भी लाभ मिलेगा। जिसमे कर्मचारियों को डेढ़ गुना वेतन मिलेगा। इसके साथ व्यापारी के वहां ३० का स्टाफ होगा ऐसी दुकानें, शॉप या मॉल में महिलाओं को ध्यान में रखकर घोडियाघर बनाये जाएंगे। १०० से ज्यादा कर्मचारी हो ऐसी जगह पर केन्टीन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 and Published from TF-01, Nanakram Super Market,Ramnager,Sabarmati, Ahmedabad - 380 005.Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH